संख्या–15 भा0स0 / क0नि0प्र0 / 26–3–2014–14(01) / 2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊ:दिनांक: 19 फरवरी,2014

विषयः– हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम–2013 के सम्बन्ध में।

महोदय,

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम–2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है जो दिनांक 06–12–2013 से देश के सभी राज्यों (जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर) में प्रभावी हो गया है।

2– उक्त अधिनियम के कियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–108 / क0नि0प्र0 / 26–3--2014–13(60) / 2013 दिनांक 10 फरवरी,2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अधिनियम की धारा–13 में चिन्हित मैनुअल स्केवेन्जरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिये जाने तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनका पुनर्वासन कराये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा–13 (1) (ए) (ii) में चिन्हित मैनुअल स्केवेन्जर्स को एकबारगी एकमुश्त नकद सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि अधिनियम की उक्त एकमुश्त नकद सहायता सम्बन्धी प्राविधान के अनुक्रम में एकमुश्त नकद सहायता की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा संशोधित एस0आर0एम0एस0 (मैनुअल स्कैवेन्जर्स के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना) के अन्तर्गत की गयी है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–05भा0स0 / क0नि0प्र0 / 26–3–2014–14(1) / 2014 दिनांक 06–02–2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये है। संशोधित एस0आर0एम0एस0 योजना में एकबारगी सहायता के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:–

एकमुश्त वित्तीय सहायताः–

प्रत्येक परिवार से अभिज्ञात हाथ से मैला उठाने वाला केवल एक कर्मी अभिज्ञात किए जाने के तुरन्त बाद 40,000 रू0 की एकबारगी नकद सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। एक परिवार से केवल एक ही हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के रूप में अभिचिन्हित व्यक्ति को उक्त एकमुश्त सहायता प्रदान की जोयगी। लाभार्थी को अधिकतम् 7,000 रू0 की मासिक किश्तों में राशि निकालने की अनुमति होगी। लाभार्थी मैनुअल स्कैवेन्जर के बैंक खाते आदि का विवरण और UIDAI विवरण (यदि उपलब्ध हो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जिससे एकबारगी नकद सहायता की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सके। धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुदान, ब्याज अनुदान एवं वृत्तिका के लिए पात्र होगा। हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के आश्रित प्रारम्भिक नकद धनराशि के लिए पात्र नहीं होगें।

4– एकमुश्त सहायता की धनराशि इस हेतु अर्ह पाये गये चिन्हित स्वच्छकार के खाते में भारत सरकार की एजेन्सी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। संयुक्त सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–19014/63/2013–एस0सी0डी0–4 दिनांक 10 फरवरी,2014 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा एकबारगी नकद सहायता के लिए अर्ह पाये गये लाभार्थी मैनुअल स्केवेन्जर्स का पूर्ण विवरण यथा–बैंक विवरण (आर0टी0जी0एस0/आई0एफ0 एस0सी0/बचत अथवा चालू खाता संख्या/ब्रान्च कोड/बैंक कोड, दूरभाष संख्या, मोबाइल नं0/यू0आई0डी0 ए0आई0) सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत एकमुश्त सहायता के लिए अर्ह पाये गये चिन्हित लाभार्थी मैनुअल स्केवेन्जर्स के उक्त अपेक्षित बैंक विवरण 07 दिन के अन्दर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वांछित सूचना/विवरण भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,
19.2.14
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या–15 भा0स0 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निदेशक,स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
6– निदेशक,पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
7– निदेशक,सूडा, नवचेतना केन्द्र, अशोक मार्ग,लखनऊ।
8– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,महानगर,लखनऊ।
9– समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)/पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 उ0प्र0।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

15भा.स./क.नि.प्र./26-314

सत्यमेव जयते

Sanjeev Kumar
Telefax: 23383853

युक्त सचिव
nt Secretary

सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110 001

**MINISTRY OF SOCIAL
JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI -110001**

D.O.No. 19014/63/2013-SCD-IV

February 10, 2014

Dear Sir,

Please refer to my d.o. letter dated 2.1.2014 (**Annexure-I**) regarding implementation of the revised Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). In this regard, our Secretary also wrote to your Chief Secretary, vide d.o. letter dated 3.2.2014 (**Annexure-II**).

2. The National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC) has requested the Scheduled Castes Development Corporation of your State, being the State Channelizing Agency (SCA), for taking action and furnishing information, as follows, as per revised SRMS for rehabilitation of identified manual scavengers in the State:-

- Uploading of complete details of identified manual scavengers on the website of www.mssurvey.nic.in), designed by our Department, for Survey of Manual Scavengers in Statutory Towns.
- Furnishing proposal, through the State Government, for:-
  - a. transferring the onetime cash assistance of Rs.40,000/- directly in the accounts of the eligible Manual Scavengers alongwith furnishing complete bank details of identified manual scavengers who qualify for being provided one time cash assistance, which include RTGS/IFSC/A/c. No., Branch Code, Bank Code, A/c. No. (SB/CA), name of the Bank alongwith address & telephone numbers), UIDAI, if any.
  - b. conducting Skill Development Training Programmes and Rehabilitation of identified Manual Scavengers under SRMS.
- To provide a copy of Identity Cards of identified Manual Scavengers and a certificate to the effect that the Manual Scavengers have been identified as per the provisions of the 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013(MS Act).

2....

3. I would request you to please have the above mentioned information furnished to NSKFDC so that it may immediately process the cases for crediting the amount of one time cash assistance in the bank accounts of the eligible beneficiaries, and also release the funds to the SCA for skill development training programmes & self employment projects of the willing and eligible manual scavengers.

Yours sincerely,

(Sanjeev Kumar)

Encl: As above.

Shri Sunil Kumar,
Principal Secretary,
Social Welfare Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow-226 001.

Annexure-I

न सचिव
Secretary
ev Kumar
x: 23383853

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI -110115

.O.No. 19014/63/2013-SCD-IV

January 2, 2014

ear

Please refer to our letter No. 19014/07/2011-SCD-IV dated 2.12.2013 sending erewith a copy of revised Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual cavengers (SRMS), which has become applicable from November, 2013.

The National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC), e Apex Corporation of this Ministry would be the nodal Central agency for implementation the Scheme in all States/UTs. You are, therefore, requested to nominate a suitable State hennelising Agency for implementation of the Scheme and issue appropriate directions to mediately take action for implementation of the revised Scheme.

I would like to emphasise that Section 13 of the "Prohibition of Employment as anual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013", which has come into force w.e.f. 12.2013, inter alia, provides for rehabilitation of identified manual scavengers and their ependents, inter alia, in the following manner:-

(i) One time cash assistance, within one month of identification to one family member engaged in manual scavenging;

(ii) Training with stipend of atleast @ Rs. 3,000 per month;

(iii) Concessional loan with subsidy for taking up alternative occupation;

Revised SRMS Scheme is in syncronisation with the said Act.

Accordingly, you are requested to ensure, inter alia, the following immediate action y your State:-

(i) Furnish proposal of your States/UTs to the NSKFDC for providing assistance to beneficiaries under the revised SRMS Scheme.

(ii) make arrangements for organising camps to provide single window for rehabilitation under SRMS.

(iv) Obtain and utilise the extensive list of viable and effective training programmes and projects for sustainable rehabilitation, being prepared by NSKFDC.

(iv) Submit the proposals for training or projects to NSKFDC for scrutiny by them, who while sanctioning training or project, would ensure their viability and effectiveness for sustainable rehabilitation. I have requested NSKFDC to complete the scrutiny of training and project proposals within 5 working days of receipt

(v) In case any trainee requires project for rehabilitation, his/her project should be got sanctioned before completion of his/her training

(vi) Section 13(1)(a)(ii) of the MS Act provides for payment of one-time cash assistance, within one month of identification of a manual scavenger according to the provisions of the Scheme, for which the following action would be required to be taken:-

a. ensure that only one manual scavenger from a family gets one time cash assistance.

b. Furnish the bank details and UIDAI details (if available) of each beneficiary manual scavenger to NSKFDC so that the amount of one-time cash assistance is directly credited into the bank account of the beneficiary.

5. Therefore, immediate arrangements may please be made for providing one-time cash assistance to the identified manual scavengers, after completion of the survey of manual scavengers in the State/UT. It needs to be ensured that the list of manual scavengers is prepared in consonance with the definition of manual scavengers contained in the Act.

6. I would be grateful, if you could please ensure immediate action as per action points in paras 2 to 5 above.

(Sanjeev Kumar)

Secretaries/Pr. Secretaries of States – as per list enclosed.,

Annexure-II

मार्ग
HIR BHARGAVA

ETARY
23382683, Fax : 23385180
l : secywel@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Deptt. of Social Justice and Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi -110 001

D.O. No. 19014/63/2013-SCD-IV February 3, 2014

Dear

Please refer to our letter dated 2.1.2014 (copy enclosed) addressed to the concerned Pr. Secretary/Secretary of your State/UT dealing with Welfare of Scheduled Castes regarding implementation of the Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), which has been revised in consonance with the provisions of the 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013' (MS Act).

2. It was requested, inter alia, to furnish proposal of your State/UT, under SRMS to the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation for seeking assistance under the SRMS for rehabilitation of identified manual scavengers. However, the proposal is yet to be received.

3. During a meeting held at New Delhi to review the implementation of MS Act, representative of your State informed that _____ (data as per attached sheet) manual scavengers were identified during the ongoing survey of manual scavengers in statutory towns. In this regard, I would like to emphasize that as per Sections 11, 12, 14 and 15 of the MS Act, survey of manual scavengers is to be carried out, both, in urban and rural areas as per the provisions of the Act and the manual scavengers so identified are to be immediately rehabilitated.

4. I would be grateful if you could get necessary instructions issued to the concerned department to complete the survey of manual scavengers as per the provisions of the MS Act and also furnish proposal for seeking assistance under SRMS for rehabilitation of the identified manual scavengers.

With regards,

Yours sincerely,

Encl.: As above.

(Sudhir Bhargava

Chief Secretaries of Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, UP, Uttarakhand and West Bengal (9).